एफएमडीए नामक दुकान में खाने-कमाने का धंधा शुरू

बेईमान और बदनाम लोग चले हैं ग्रेटर फरीदाबाद की किस्मत बदलने

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: एफएमडीए (फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण) की आड़ में खाने-कमाने का धंधा शुरू हो गया है। ग्रेटर फरीदाबाद को मेन मथुरा रोड और एनआईटी से जोड़ने के लिए 6 पुल पहले से ही बने हुए हैं। इसके अलावा कालिन्दी कुंज दिल्ली से भी ग्रेटर फ़रीदाबाद की बेहतरीन कनेक्टीविटी है। इसके बावजूद पश्चिमी फरीदाबाद (एनआईटी और अरावली जोन) को ईस्ट फरीदाबाद (ग्रेटर फरीदाबाद यानी नहरपार) से जोड़ने के नाम पर नया रास्ता तरीका खोजा गया है। एफएमडीए की बैठक करने 1 जून को इसके सीईओ सुधीर राजपाल जो चंडीगढ़ बैठते हैं, फरीदाबाद आए। चूंकि विभिन्न एजेंसियों को 1 जून वाली बैठक की जानकारी नहीं थी तो 2 जून को फिर से बैठक रखी गई। 1 जून की बैठक के बाद सुधीर राजपाल ने ग्रेटर फरीदाबाद को एनआईटी और मथुरा रोड से जोड़ने की रूपरेखा मीडिया को बताई। लेकिन किसी पत्रकार ने यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि जब 6 पुल पहले से बने हुए तो कनेक्टीविटी के नाम पर यह नया तमाशा क्यों किया जा रहा है।

इतनी सिविक एजेंसियां, कितना विकास

फरीदाबाद में नगर निगम और हूडा पहले से ही हैं। खट्टर सरकार ने कुछ नया करने के नाम पर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लांच कराया। इसके लिए अलग से एक आईएएस गरिमा मित्तल को सीईओ बनाते हुए उन्हें फरीदाबाद के विकास की जिम्मेदारी दे दी। स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह-जगह शहर को खोद डाला गया लेकिन फरीदाबाद का विकास नहीं हो सका। इसके बाद 10 अप्रैल 2021 को सीएम खट्टर फरीदाबाद आए और उन्होंने एफएमडीए की घोषणा की। हालांकि हरियाणा विधानसभा में 28 दिसंबर 2018 में एफएमडीए बनाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो गया था लेकिन पिछले दो साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ। एफएमडीए की घोषणा के साथ बताया गया कि एमसीएफ और हूडा के कुछ काम एफएमडीए को मिलेगा, जिसमें सड़क और पेयजल प्रमुख है। गरिमा मित्तल को एफएमडीए का भी अतिरिक्त सीईओ घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के करीब 22 दिन बाद सुधीर राजपाल भी घोषणा करने आए लेकिन इस बार अफसरों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा खर्च करने का जुगाड़ कर लिया।

एफएमडीए के नाम पर अभी तक सिर्फ बैठकें ही हुई। 10 अप्रैल को हुई बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री

धंधेबाज डॉक्टर, प्रॉपर्टी डीलर हैं सलाहकार

एफएमडीए का सलाहकार अभी तक तीन लोगों को बनाया गया है। ये हैं - डॉ एस. एस. बंसल (एसएसबी अस्पताल), बी. आर. भाटिया (उद्योगपति), अमित भल्ला (प्रॉपर्टी डीलर- मानव रचना का मालिक)। अभी तीन और लोगों की नियुक्ति अभी की जानी है।

रात-दिन रोगियों के बीच व्यस्त रहने वाले डॉ बंसल शहर की तरक़्क़ी के लिए कितना सोच पाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन उनकी नियुक्ति का आधार अगर ये है कि वे किसी तरह मुख्यमंत्री खट्टर के नज़दीक पहुँच गए हैं तो अलग बात है। पिछले दिनों मेट्रो अस्पताल में मैनेजमेंट परिवर्तन और मथुरा रोड स्थित क्यूआरजी अस्पताल की बिक्री में जिस तरह खट्टर ने डॉ बंसल और डॉ पुरुषोत्तम के बीच बिचौलिये की भूमिका निभाई थी जगज़ाहिर है। वही क्यूआरजी अब एसएसबी बन गया है।

एफएमडीए के सलाहकार अमित भल्ला मूल रूप से प्रॉपर्टी डीलर है। उसके पिता भी प्रॉपर्टी डीलर थे। पिता-पुत्र ने पूरे अरावली ज़ोन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरावली में पर्यावरण के असंख्य नियम तोड़ने वाला कोई प्रॉपर्टी डीलर एफएमडीए को जो सलाह देगा, उसे समझना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। अमित भल्ला के पिता भी शहर में प्रॉपर्टी डीलरों का कर्टेल चलाते थे और वहीं काम अमित भल्ला का भी है। अमित भल्ला के कर्टेल में कई मंत्री-संत्री तक शामिल हैं। ये लोग एफएमडीए को अगर कोई सलाह भी देंगे तो वह अपने हित साधने के लिए ही होगी। इसी ज़िले में अमित भल्ला से भी बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी जगह अमित भल्ला को लेकर खुद सरकार ने एफएमडीए की साख को धक्का पहुँचाया है।

उद्योगपति बी. आर. भाटिया को महज़ फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का प्रधान होने की वजह से सलाहकार रखा गया है। जबकि इसी शहर में भाटिया से भी बड़े उद्योगपति रहते हैं। लेकिन एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर एडजस्ट किया गया है। हैरानी तब होती है जब यही बी. आर. भाटिया व्यापारी नेता बनकर भी सीएम से मिलने पहुँच जाते हैं। खट्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले ये लोग ग्रेटर फ़रीदाबाद और फ़रीदाबाद की चिन्ता करेंगे, इसमें संदेह है।

जो फर्म ईस्ट और वेस्ट फरीदाबाद को कथित तौर पर जोड़ने के लिए अनुबंधित की जाएगी, उसके ग्लोबल टेंडर जारी करने कने का ऐलान 1 जून को हुआ है। इस पर करीब सवा करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यानी सवा करोड़ रुपये खर्च होने के बाद फरीदाबाद की जनता को यह पता चलेगा कि कितने और पुल या फ्लाईओवर ईस्ट और वेस्ट के बीच बनेंगे। जाहिर है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि हूडा के पास सारी सर्वे रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है। आखिर ग्रेटर फरीदाबाद का विकास हूडा ही कर रहा है। इस तरह बीस-तीस लाख रुपये में एफएमडीए की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी जाएगी। शेष पैसे अफसरों की जेब में जाएंगे। इसमें दो-चार मनमोहक मॉडल भी सीएम को रिझाने के लिए बना दिए जाएंगे।

सीवर का पता नहीं, 2041 तक सोच लिया

ग्रेटर फरीदाबाद में आज भी सीवर लाइन नहीं बिछ पाई है और यहां के सोससाइटियों से इकट्ठा किया गया मल यमुना में बहाया जाता है। ग्रेटर फरीदाबाद की इस समय सबसे बड़ी जरूरत सीवर लाइन, सड़कों का जाल, बेहतर पेयजल सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ट्रांसपोर्ट है लेकिन अफसरों को सबसे पहले कनेक्टीविटी में जो मलाई दिख रही है, वो और कहीं नजर नहीं आ रही है। मलाई खाने की शुरुआत प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने से होगी और जब पुल या एलिवेटेड कॉरिडोर पास होगा तो उसमें भी मोटा कमीशन आना ही है। बहरहाल, एफएमडीए ने हवा में तलवार भांजते हुए 2041 तक के हिसाब से प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी 2041 में जितनी आबादी ग्रेटर फरीदाबाद में होगी, उसके हिसाब से यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और जनसुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। हरियाणा सरकार और बदमाश अफसरों को कोरोना महामारी के बावजूद यह अक्ल नहीं आई की ग्रेटर फरीदाबाद में सबसे पहले आला दर्जे की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए।

कई नावों पर सवार अधिकारी

एफएमडीए का सीईओ चंडीगढ़ बैठता है। एफएमडीए की अतिरिक्त सीईओ गरिमा मित्तल एकसाथ एमसीएफ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और एफएमडीए संभाल रही हैं। इसी से पता चलता है कि सरकार एफएमडीए को लेकर इतना गंभीर है कि वो यहाँ फुलटाइम अधिकारी और कर्मचारी तक नियुक्त तक नहीं कर पा रहा है। हाल ही में दो इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है लेकिन उन्हें भी डेपुटेशन पर लाया गया है। इसी तरह एमसीएफ और हूडा से कुछ और अधिकारी- कर्मचारी यहाँ डेपुटेशन पर लाये जायेंगे। डेपुटेशन पर आने वालों का इतिहास रहा है कि वे खा-कमाकर निकल लेते हैं। उनकी दिलचस्पी उस एजेंसी को ऊँचाई पर ले जाने में नहीं होती। एमसीएफ और हूडा के कई बदनाम और भ्रष्ट अधिकारी एफएमडीए में आने को छटपटा रहे हैं। क्योंकि एफएमडीए को सीएलयू करने का सीधा अधिकार होगा। बहरहाल, एक साथ तीन एजेंसियों का काम संभाल रही गरिमा मित्तल का हाल अब ये है कि वो किसी एक एजेंसी के लिए टिक कर फ़ैसले नहीं ले पा रही हैं। एमसीएफ में उनका मन लगता ही नहीं है। नतीजा एमसीएफ रामभरोसे है। हालाँकि एमसीएफ ही फ़रीदाबाद के विकास के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन वो अपने कर्मचारियों का वेतन ही नहीं निकाल पा रहा।

फ़रीदाबाद पुलिस की 'बिना मास्क चालान सेवा' जारी है

सरकारी पास होने, मास्क पहनने के बावजूद कर रहे हैं कार्रवाई

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद- लॉकडाउन के दौरान पास होने के बावजूद लोगों को परेशान करने से फ़रीदाबाद पुलिस मान नहीं रही है। हालाँकि सरकार अब कुछ ढील दे रही है लेकिन फरीदाबाद पुलिस को कोई भी ढील मंजूर नहीं है। सतीश नागपाल के साथ हुई घटना इसका उदाहरण है।

भुपानी पुलिस ने 1 जून को सतीश का चालान उस वक्त काट दिया जब वह अपनी टैक्सी से आवश्यक सामान पहुँचाने कहीं जा रहे थे। उनके पास पास लॉकडाउन में टैक्सी चलाने का सरकारी पास होते हुए भी उनका 500 रूपये का चालान पुलिस ने काटा।

ड्राइवर सतीश

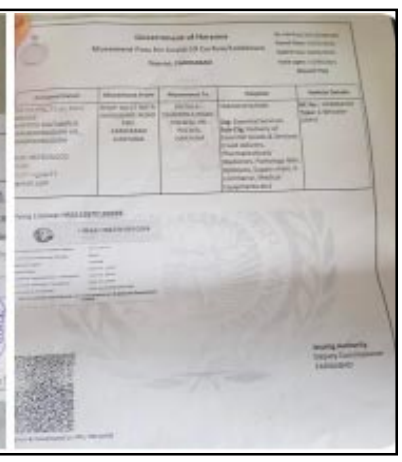

पुलिस ने उन्हें चालान की जो रसीद थमाई है, उस पर मास्क न पहनने अथवा सार्वजनिक स्थल पर थूकने का आरोप लिखा है। पुलिस ने दोनों में से किसी पर टिक नहीं लगाया है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ड्राइवर सतीश ने मास्क लगा रखा था और गाड़ी के अंदर थे, इसलिए कहीं थूक भी नहीं रहे थे। फ़ोटो में चालान की रसीद का नंबर और चालान बुक नंबर लिखा हुआ है।

भुपानी पुलिस के जिन पुलिसकर्मियों ने सतीश का चालान काटा है उनके पास ट्रैफ़िक नियम तोड़ने का चालान काटने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपदा में अवसर तलाशते हुए इन लोगों ने मास्क न पहनने वालों का चालान काटने के लिए मिली चालानबुक को ढाल बना लिया है।

सतीश के पास जो चालानबुक है उसका नंबर 1431 है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़रीदाबाद पुलिस कितने बड़े पैमाने पर मास्क न पहनने का चालान दूसरे नियम तोड़ने के बदले में काट रही है। लेकिन ये पैसा कहाँ जमा हो रहा है, अब तक कितना पैसा जमा कराया गया और कितने चालान इस तरह के काटे गए उस ब्योरे को फ़रीदाबाद पुलिस ने जारी नहीं किया है। अगर पुलिस को इस चालान टारगेट के बदले सरकार से कोई कमीशन मिलता है तो उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस संबंध में कई समाजसेवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरटीआई लगाई थी लेकिन पुलिस ने किसी का जवाब नहीं दिया है।

इस संबंध राज्य के सूचना आयुक्त के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। मज़दूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि पिछले अंकों में हमने फ़रीदाबाद पुलिस की चालान सेवा के बारे में विस्तार से छापा था।